

**कार्यालय उ०प्र० सूचना आयोग, आर.टी.आई. भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ**


पत्रांक: ५०२/रा०सू०आ०/मु०सू०आ०/२०२६

दिनांक: १५ जून, २०२६

आदेश

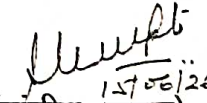
मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा किशन चन्द जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य रिट पिटिशन सं०-(सिविल) ३६०/२०२१ में दिये गये आदेश के अनुपालन में मा० मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा निर्गत पत्रांक: २३/रा०मु०सू०आ०/रा०सू०आ०/२०२३-२४ दिनांक २७ अगस्त, २०२४ के माध्यम से दिनांक १९.०८.२०२४ के बाद से ऑफलाइन डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील/शिकायत आवेदन पत्रों को आदेश दिनांक ११.०७.२०२४ सपठित आदेश दिनांक २७.०७.२०२४ के अनुक्रम में मा० आयोग में द्वितीय अपील/शिकायतों को ऑफलाइन दाखिल करने पर (कुछ अपवादों को छोड़कर) पूर्णतः रोक लगा दी गयी थी।

उक्तानुसार मा० उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था एवं उ०प्र० शासन की पेपरलेस नीति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि ऐसी पत्रावलियाँ / वाद जो पूर्व में मा० आयोग में प्रचलित ऑफलाइन व्यवस्था के तहत निस्तारित की गयी हैं, में यदि नवीन रीकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो वह आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.upsic.up.gov.in पर दी गयी व्यवस्था के तहत ऑनलाइन रूप से दिनांक १७.०६.२०२६ से नियमानुसार प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए आवेदन किया जायेगा। ऑफलाइन रूप से प्रेषित रीकॉल प्रार्थना पत्र आयोग में दिनांक १७.०६.२०२६ से स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


(डॉ० राजकुमार विश्वकर्मा)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निजी सचिव, मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
२. निजी सचिव, समस्त मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
३. सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
४. CATS डेवलपमेंट टीम को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आयोग की वेबसाइट पर उक्त व्यवस्था को लाइव करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
५. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आयोग की पुराने साफ्टवेयर पर पूर्व रीकॉल व्यवस्था को पूर्णतः बन्द करते हुए तत्सम्बन्ध में आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।


(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार